बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 187 ● नई दिल्ली ● सोमवार 11 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली में आइएसआइ एजेंट और गैंगस्टर सहयोगी प्रवीण कुमार गिरफ्तार, विदेशी हथियारों की तस्करी का खुलासा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के एजेंट अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर और आतंकी मोड्यूल के एक और सदस्य प्रवीण कुमार उर्फ टिट्टू को गिरफ्तार किया है। वह दक्षिण दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर रोहित चौधरी का करीबी सहयोगी है। इसपर पूर्व में दो लाख का इनाम था। मकोका में बंद रोहित चौधरी पिछले साल मई में जमानत पर बाहर आया था। उसके बाद अक्टूबर में उसकी दुबई में शाहबाज अंसारी के साथ विदेशी हथियारों की डील हुई थी। डील होने के बाद प्रवीण के जरिये वह अंसारी से हथियार मंगवा रहा था। सूत्रों के मुताबिक अंसारी के साथ लिंक जुड़ने पर क्राइम ब्रांच ने जब रोहित चौधरी को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू की तब यूएपीए से बचने के लिए वह 2019 के फर्जी पासपोर्ट मामले में स्पेशल सेल में समर्पण करने की कोशिश कर रहा है।

पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश बेंगलुरु में कार्यक्रम स्थल के पास मिला विस्फोटक

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु यात्रा से पहले रविवार (10 मई, 2026) को शहर के बाहरी इलाके में स्थित कार्यक्रम स्थल से थोड़ी दूर पर दो जिलेटिन स्टीक्स बरामद किए गए हैं. पीएम के कार्यक्रम स्थल के नजदीक जिलेटिन स्टीक्स के बरामद किए जाने के बाद सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है. यह विस्फोटक बेंगलुरु के कागलीपुरा के पास एक आश्रम के नजदीक मिली, जो मुख्य कार्यक्रम स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर था, जिसमें पीएम मोदी शामिल होने वाले थे. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विस्फोटक की बरामदगी के बाद बेंगलुरु सेंट्रल रेंज के डीआईजी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले की जा रही जांच के दौरान दो जिलेटिन स्टीक्स रविवार (10 मई, 2026) की सुबह फुटपाथ के किनारे से बरामद की गईं, जो मुख्य कार्यक्रम स्थल से करीब 3 किमी दूर था, जिसमें पीएम शामिल होने वाले थे.' उन्होंने कहा, 'घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को घेर लिया है. बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया है, जहां बरामद सामग्री की जांच की गई. इस मामले में आगे की जांच फिलहाल जारी है.' यह घटना खुफिया एजेंसियों की तरफ से संभावित आतंकी खतरे की सूचना मिलने के एक दिन बाद सामने आई है.

जिसके चलते दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कई संवेदनशील स्थानों पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा, 'पुलिस को संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों, लावारिस सामानों और खड़ी गाड़ियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.' बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में गहनता के साथ अपनी जांच शुरू कर दी है और पुलिस अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिलेटिन स्टिक्स उस जगह तक कैसे पहुंचीं और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी.

विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने

शपथ लेते वक्त स्पीच देने लगे तो राज्यपाल ने टोका; पहला ऑर्डर 200 यूनिट फ्री बिजली का

चेन्नई। तमिलगा वेत्री कड़गम चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रविवार सुबह 10.15 बजे तमिल में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। थलापति विजय शपथ लेते समय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि वही पढ़ें जो लिखकर दिया है। सीएम विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. केजी अरुणराज, केए सेंगोट्टैयन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ. टीके प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना शामिल हैं। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के विधायक हैं। सहयोगी दलों के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। सीएम बनते ही विजय एक्शन में आए और दस्तावेजों का पहला सेट साइन

किया। इनमें 200 यूनिट फ्री बिजली देने, महिला सुरक्षा दल और एंटी ड्रग्स स्क्वॉड बनाने के आदेश शामिल हैं।

विजय ने शपथ के दौरान कहा- मैं सी. जोसेफ विजय भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने विवेक के अनुसार कर्तव्यों और कानून का पालन करूंगा। किसी से डरूंगा नहीं और ना ही एकतरफा आदेश मानूंगा। मैं न्याय करूंगा, सभी लोगों के साथ न्याय करूंगा।

तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने रविवार को मुख्यमंत्री पद संभालते ही तीन बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाने और पूरे राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी-ड्रग यूनिट बनाने से जुड़े दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में अपने पहले संबोधन में विजय ने कहा कि अब सच्ची धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले नए शासन की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में उनके अलावा कोई दूसरा शक्ति केंद्र नहीं होगा और वही एकमात्र शक्ति केंद्र रहेंगे। विजय ने सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी को समर्थन देने पर कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का धन्यवाद किया। उन्होंने खास तौर पर युवाओं का आभार जताया और कहा कि टीवीके की जीत में युवाओं की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने अपने परिवारों को उनकी पार्टी के लिए वोट देने के लिए मनाया।

नदी किनारे पड़े सूटकेसों में मिले कटे हुए शवों के टुकड़े, इलाके में सनसनी; मौके पर पहुंची पुलिस

कैमूर। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब दुर्गावती नदी किनारे दो संदिग्ध सूटकेश बरामद किए गए। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सूटकेश खोले, तो उनमें कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिले। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया बरामद अवशेषों में एक बच्चे और एक वयस्क व्यक्ति के शव होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं एफएसएल टीम और डीआईयू टीम भी मौके पर पहुंचकर सैंपल इकट्ठा करने और जांच में जुट गई। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि मोहनिया और रामगढ़ थाना क्षेत्र की सीमा के पास ग्रामीणों ने नदी किनारे कुछ बॉडी पार्ट्स पड़े होने की सूचना दी थी।

एक्शन में शुभेंदु अधिकारी- बंगाल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, सीएम ने पहले ही दिन लिया अहम फैसला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नवगठित शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में आने वाले महीनों में पुलिस और प्रशासनिक ढांचे में बड़े स्तर पर फेरबदल होने के संकेत मिल रहे हैं। इसकी झलक सरकार के पहले ही दिन देखने को मिल गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर राज्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय की नौकरशाही संरचना में व्यापक बदलाव किए हैं। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पूर्व केंद्रीय कार्यालय से जुड़े 16 नौकरशाहों को बदल दिया गया है। स्थानांतरित किए गए पूर्व अधिकारियों में सबसे प्रमुख नाम 2014 बैच के आईएएस शांतनु मुखोपाध्याय का है,

जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी संघ के शीर्ष नेता व केंद्रीय कार्यालय में तैनात प्रताप नायक का तबादला दार्जिलिंग जिले के बिजनबारी स्थित पालबाजार ब्लॉक विकास कार्यालय में कर दिया गया है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत 46 अधिकारियों को अस्थायी रूप से राज्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में तैनात किया गया है। इन अधिकारियों की अगली तैनाती का निर्णय बाद में लिया जाएगा।

शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों बाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रता गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं, पश्चिम बंगाल के 2017 बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रता बाला को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का प्रधान सचिव नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इससे पहले वे दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट थे। इस बीच, कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने उप-निरीक्षकों, निरीक्षकों, सहायक आयुक्तों और उपायुक्तों के पद पर कार्यरत 93 अधिकारियों का तबादला शहर पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है। स्थानांतरित अधिकारियों में से अधिकांश तृणमूल से संबद्ध पुलिस कल्याण संघ में प्रभावशाली थे। इन 93 अधिकारियों का तबादला उत्तरी बंगाल के कूच बिहार, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र के आदिवासी बहुल जिलों, जैसे बांकुरा और पुरुलिया में किया गया है।

आखिरी 9 महीनों में ये मंत्री क्या कर लेंगे जब 9 साल में ये सरकार कुछ न कर सकी, अखिलेश ने कसा तंज

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने तंज भरे लहजे में एक्स पर बयान दिया कि आखिरी 9 महीनों में ये मंत्री क्या कर लेंगे जब 9 साल में ये सरकार कुछ न कर सकी। उन्होंने एक्स पर दिए गए बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार पर जनता के विचार और सवाल - उप्र में मंत्रिमंडल में केवल 6 रिक्तियाँ हैं, इससे ज़्यादा तो दूसरे दल से पाला बदल कर आए लोग हैं, क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाज़ा जाएगा
- क्या उनमें से सबसे कमज़ोर को

चुना जाएगा जिससे कि उसकी कमज़ोरी कुछ कम हो जाए
- एक समाज के कई विधायकों में से किसी एक को चुना जाएगा तो चुनने का आधार क्या होगा
- अगर ऐसा हुआ तो बाक़ी दल-बदलुओं का क्या होगा
- उनकी उपेक्षा व अपमान को क्या कुछ ले-देकर शांत करा जाएगा
- या उन्हें भी ये अहसास करा दिया जाएगा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है
- बाक़ी छूटे हुए लोग क्या अपने को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे
- वो अपने चुनाव क्षेत्र में मुँह दिखाने लायक़ बचेंगे क्या
- इसके अतिरिक्त प्रश्न ये भी है कि उनके अपने दल के जो लोग मंत्री बनने के इंतज़ार में सूखकर काँटा हो गये हैं, उन बेचारों का क्या होगा
- जिन वर्तमान मंत्रियों के विभाग कम किये जाएंगे तो क्या इससे जनता के बीच ये संदेश नहीं जाएगा कि वो नाकाम रहे, इसलिए उनसे मंत्रालय छीन लिया गया है
- ऐसे मंत्री तो बिना लड़े ही क्या अपना चुनाव हार नहीं जाएंगे
- साथी दलों को प्रतीक्षा के स्थान पर और कुछ मिलेगा या फिर उनको ये कहकर उपेक्षित कर दिया जाएगा
तुम थे जिनके सहारे, वो हुए न तुम्हारे

वो तो ठग है पुराने तुम ये सच न जाने और हाँ जनता ये भी पूछ रही है कि आख़िरी 9 महीनों में ये मंत्री क्या कर लेंगे जब 9 साल में ये सरकार कुछ न कर सकी। ये भी केवल वही करेंगे जो भाजपा सरकार ने किया है-
भ्रष्टाचार और अत्याचार!
पीडीए पर वार-ही-वार!
महंगाई-बेकारी की मार!
ये जीना कर देंगे दुश्वार!

चल चाणक्य अब पंजाब, जीत लिया बंगाल

या-रब ये विरोधी न समझे है, न समझेंगे मोदी जी के मन की बात। बताइए, बंगाल फतेह करने के बाद, मोदी जी फौरन अपना वादा पूरा करने में जुट गए कि नहीं कि नहीं मोदी जी ने अपने वादे बल्कि अपनी गारंटी को पूरा किया कि नहीं कि बंगाल में, बंगाली को गद्दी पर बैठाएंगे; बांग्ला बोलने वाले को गद्दी पर बैठाएंगे; कोलकाता में राज करने वाले को बंगाल की गद्दी पर बैठाएंगे। लेकिन, मजाल है कि एक बार फिर बाहर वालों के राज से बंगाल वालों की जान बचवाने के लिए, विपक्ष वालों ने मोदी जी को जाग को भी धन्यवाद दिया हो। उल्टे जब मोदी जी ब्रिगेड परेड मैदान में शुभेंदु अधिकारी का राजतिलक करा रहे थे, तब जिन्होंने ब्रिगेड के बाहर सोशल मीडिया पर मोदी जी का ही दस साल पुराना वीडियो वायरल कर के, खुद मोदी जी के श्रीमुख से अधिकारी को महाभ्रष्ट कहलवा रहे थे! नहीं हम यह नहीं कह रहे हैं कि अधिकारी को खुद मोदी जी की आवाज में भ्रष्ट कहे जाने से, मोदी जी को कोई फर्क पड़ता है या शुभेंदु अधिकारी जी को ही कोई फर्क पड़ता है या बंगाल में ऐसे बदलाव के यज्ञ में आहुति देने वालों को कोई फर्क पड़ता है। जैसे नारदा घोटाले का वीडियो वायरल नहीं होता तब भी शुभेंदु बाबू राजतिलक होता, वैसे ही वीडियो वायरल होने के बाद भी उनका राजतिलक हुआ। जैसे मोदी जी की आवाज में उनके घोटाले की याद दिलाए जाने के बिना, मोदी जी के आशीर्वाद से शुभेंदु बाबू का राजतिलक हुआ होता, वैसे ही खुद मोदी जी की आवाज में घोटाले की कथा पब्लिक को सुनाए जाने के बाद भी, मोदी जी के आशीर्वाद से उनका राजतिलक हुआ। वास्तव में मोदी जी की यही तो खासियत है। मोदी जी जो करने की ठान लेते हैं, वह कर के ही मानते हैं! मोदी जी ठान लेते हैं, वह करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है बल्कि अब तो कोई रोकने की जुर्रत भी नहीं करता है, न कोई अदालत-वदालत और न कोई चुनाव आयोग वगैरह। शुरू में ही दिखाई दे रहा था कि मोदी जी इस बार बंगाल को फतेह कर के मानेंगे और फतेह कर के दिखाया भी। बंगाल को फतेह करने के लिए, मोदी जी को चुनाव आयोग को अपने युद्ध-रथ में जोतना पड़ा, तो जोता। ईडी, सीबीआई, केंद्रीय बलों, सब को काम पर लगाना पड़ा, तो लगाया। धनसेठों की तिजोरियों से निकला पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा तो बहाया। देश की पूरी सरकार को महीनों कोलकाता ले जाकर बैठाना पड़ा तो बैठाया। साम-दाम-दंड-भेद, हरेक हथियार खुलकर आजमाया, पर बंगाल फतेह कर के दिखाया। और अब शुभेंदु अधिकारी को गद्दी पर भी बैठा दिया। मोदी जी का फैसला न टलना था और न टला। बस इतनी बात है कि खुशी के मौके पर ऐसा वीडियो वायरल हो जाए, तो मुंह का जायका जरा बिगड़ जाता है। कहां मोदी जी के आशीर्वाद से इतिहास बन रहा था और कहां चोर-चोर के शोर को दबाने के लिए, शुभेंदु अधिकारी को भगवा वेश से लेकर जय श्रीराम के नारे तक का सहारा लेना पड़ रहा था। हिंदू राज में ऐसा होना चाहिए था क्या और ये विरोधियों ने उधार का मुख्यमंत्री, उधार का मुख्यमंत्री क्या लगा रखी है शुभेंदु अधिकारी, पहले ममता बनर्जी की पार्टी में रहे थे, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि उन्हें मोदी जी की पार्टी में उधार का मुख्यमंत्री कहा जाएगा। वैसे भी यह कोई पहला मौका थोड़े ही है जब, मोदी जी ने दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में आकर जनता की सेवा करने का चांस दिया है। शुभेंदु अधिकारी को तो अब गद्दी मिली है, बगल में गुवाहाटी की गद्दी पर मोदी जी के आशीर्वाद से हिमंत बिस्वा शर्मा तो पांच साल पहले से बैठा है। वह कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। मणिपुर के पिछले मुख्यमंत्री, बीरेन सिंह भी कभी कांग्रेस में ही हुआ करते थे। और बिहार के नये-नये बने मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी चौधरी तो बिहार की करीब-करीब सभी पार्टियों में चक्कर लगाने के बाद, आखिर में मोदी जी की पार्टी में पहुंचे हैं। असल में मोदी जी पार्टियों के विभाजन से ऊपर, उठकर देश के हित को देखते हैं। मोदी जी किसी नेता की पार्टी देखते ही नहीं हैं, जैसे अर्जुन निशाने की मछली की सिर्फ आंख देखता था, वैसे ही मोदी जी तो नेताओं की सिर्फ देश की सेवा की लगन देखते हैं और देश की सेवा के लिए संसाधन जुटाने की प्रतिभा। और जहां भी उन्हें राष्ट्र के काम की कोई प्रतिभा दिखाई देती है, उसे अपनी पार्टी में लाने में और राष्ट्र वाली संघ की सेवा में लगाने में, जरा भी देरी नहीं करते हैं। यह उधार के मुख्यमंत्री, मंत्री वगैरह का नहीं, राष्ट्रहित में देश भर से राजनीतिक प्रतिभाओं का संकलन करने का मामला है। जाहिर है कि इस काम में भी बाधाएं आती हैं, पर मोदी जी बाधाओं के सामने पीछे हटने वालों में नहीं हैं। राष्ट्रहित के लिए वे तब भी, दूसरी पार्टियों के नेताओं को खींचकर अपने साथ लाना आसान थोड़े ही होता है राष्ट्र सेवा के लिए भी अक्सर लोगों को धकेलना पड़ता है। प्रलोभन भी काम नहीं आए तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई वगैरह को छोड़ना पड़ता है। मामले-मुकदमे करने पड़ते हैं। जेल का डर दिखाना पड़ता है और कभी-कभी तो जेल भेजना भी पड़ता है। इस सब के लिए, भ्रष्टाचार वगैरह के सच्चे-झूठे आरोप लगाने ही पड़ते हैं। पर यह सब तभी तक के लिए होता है, जब तक बंदा खूंटा तुड़ाकर, मोदी जी के थान पर आ नहीं पहुंचता है। जाहिर है कि उसके बाद सब भुला दिया जाता है। विरोधी इसके बाद भी, मोदी जी के आवाज के वीडियो पकड़कर बैठे रहना चाहते हैं, तो मोदी जी क्या कर सकते हैं? और हां! उधार के नेताओं से याद आया, पंजाब के लिए भी मोदी जी को अपनी पार्टी का पहला सीएम मिल गया लगता है। जैसे शुभेंदु अधिकारी कभी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो का खासमखास हुआ करता था, वैसे ही पंजाब में भी मोदी जी ने आप पार्टी सुप्रीमो का खासमखास खोज भी निकाला है और खरीद भी लिया है—वही राघव चड्ढा और कौन बंगाल फतेह हो लिया, अब पीएमओ और गृह मंत्रालय, कोलकाता से उठकर चंडीगढ़ की तरफ निकल सकते हैं। ईडी, सीबीआई की टीमों के रूप में उनकी अग्रिम पार्टियों ने पहुंच कर अपना काम शुरू भी कर दिया है। अगला नंबर पंजाब का है। तुम कहां रह गए, ज्ञानेश।

बंगाल में शुभेन्दु राज

पश्चिम बंगाल में पहली बार शुभेन्दु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से राज्य में परिवर्तन चक्र पूरा हो चुका है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शुभेन्दु अधिकारी ने 5 मंत्रियों के साथ नई पारी की शुरूआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में हुए शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही बंगाल में भगवा बयार शुरू हो गई है। जिस पश्चिम बंगाल में भाजपा की नींव जनसंघ के रूप में पड़ी उस राज्य में 75 वर्षों बाद शुभेन्दु अधिकारी भाजपा के शुभंकर साबित हुए हैं। शुभेन्दु अधिकारी कोई अचानक उभरे नेता नहीं हैं। यह कहानी उस राजनेता की है जिसने बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से देखा, समझा और फिर उसी राजनीति की दिशा बदल दी। ईस्ट मेदिनीपुर के कांथी की गलियों से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले इस नेता के पिता शिशिर अधिकारी तीन बार सांसद रहे और यूपीए 2 सरकार में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री भी रहे। शुभेन्दु ने कांग्रेस से अपना करियर शुरू किया, कांथी के काउंसिलर बने और 1998 में तृणमूल का दामन थामा लेकिन असली कहानी शुरू होती है साल 2007 से। नंदीग्राम की धरती आक्रोशित नारों और विरोध की आवाजों से गूंज रही थी। वामपंथी सरकार के प्रस्तावित केमिकल हब के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन धीरे-धीरे जनविद्रोह में बदल रहा था। उसी दौर में शुभेन्दु अधिकारी गांव-गांव घूमकर लोगों को संगठित कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक आज भी मानते हैं कि नंदीग्राम आंदोलन सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीतिक वापसी का आधार नहीं था बल्कि शुभेन्दु अधिकारी के राजनीतिक व्यक्तित्व का जन्म भी वहीं हुआ था। जिस आंदोलन में ममता बनर्जी को तीन दशक पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ने के लिए ताकत दी उसी आंदोलन ने शुभेन्दु को बंगाल की राजनीति का अपरिहार्य चेहरा बना दिया। शुभेन्दु अधिकारी विधायक बने, सांसद बने, फिर मंत्री बने। कभी वह ममता बनर्जी सरकार में नम्बर दो भी बने। राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल होता है। इसलिए सत्ता के गलियारों में समीकरण भी बदलते रहते हैं। तृणमूल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के उदय के साथ ही जब शुभेन्दु अधिकारी को महसूस हुआ कि जिस सम्मान के वे पात्र हैं वह उन्हें नहीं दिया जा रहा तो उन्होंने 2020 में भाजपा का दामन थाम लिया। शुभेन्दु अधिकारी ने भाजपा में रहकर हिन्दुत्व की विचारधारा को अपने आक्रामक तेवरों के साथ अपनाया। अपनी हिन्दुत्ववादी छवि के कारण वे राज्य में भाजपा के सबसे प्रमुख तूफानी नेता बन गए। उन्होंने खुद को हिन्दुत्व के फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित किया। उन्हें बंगाल का योगी भी कहा जाता है। शुभेन्दु अधिकारी एक बार नहीं दो बार ममता बनर्जी को उन्हीं के सियासी गढ़ में मात दे चुके हैं। किसी मुख्यमंत्री को उसकी ही सीट पर हरा देना आसान बात तो नहीं होती। हालांकि शुभेन्दु अधिकारी ने ऐसा कर दिखाया और फिर बीजेपी नेतृत्व ने भी उनके नाम पर मोहर मार दी। कोलकाता जिले की भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का पुराना गढ़ रही है। नंदीग्राम में भी शुभेन्दु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2021 में हराया था। इसके बाद वह लौटकर भवानीपुर आ गईं। इससे उन्होंने साबित कर दिया कि वह ममता बनर्जी को कहीं भी सीधी चुनौती दे सकते हैं। या यूं कहें कि बीजेपी को ममता बनर्जी का एक तगड़ा तोड़ मिल गया। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में भी असम की तरह हेमंता बिस्वा सरमा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए था। ऐसे में भाजपा के पास शुभेन्दु अधिकारी बेहतर विकल्प के रूप में सामने थे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पहली पसंद वे ही थे। शुभेन्दु अधिकारी के मुख्यमंत्री के रूप में चयन की घोषणा बंगाल की राजनीति में एक युगारम्भ, एक युगांत की तरह थी। राजनीति का चक्र कितना विचित्र होता है कि जो कल सिपाही होता है वह राजा बनकर उभरता है। नंदीग्राम के धूल भरे गलियारों से चलकर शुभेन्दु अधिकारी राईटर्स बिल्डिंग तक पहुंच चुके हैं और राज्य अब उनके नाम के साथ नया अध्याय लिखने को तैयार है। शुभेन्दु अधिकारी के सामने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की बड़ी चुनौतियां सामने हैं। अब उन्हें उन सभी मुद्दों को प्राथमिकता में रखना होगा जिन पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और जीता। भाजपा ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने और समान नागरिक संहिता लागू करने, राज्य में गुंडाराज खत्म करने, महिला सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने, संस्थागत भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने, संदेश खाली प्रकरण और आरजीकर मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेप और मर्डर मामले की जांच के लिए आयोग बनाने का वादा किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुभेन्दु अधिकारी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए हर सम्भव कदम उठाएंगे और उनकी सरकार तुष्टिकरण की नीतियों को छोड़ कर जनता को स्वच्छ, ईमानदार प्रशासन देंगे और राज्य को भयमुक्त बनाएंगे। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शुभेन्दु अधिकारी बंगाल को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या वे भाजपा के वैचारिक एजैंडे को बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा के साथ संतुलित कर पाएंगे। बंगाल के लोगों को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परम्पराओं से बहुत स्नेह है और बंगाल की अस्मिता उनके लिए महत्वपूर्ण है। देखना यह भी है कि शुभेन्दु उस राज्य में स्थिरता ला पाएंगे, जहां दशकों से राजनीति संघर्ष और टकराव की जमीन रही है। उम्मीद है कि राज्य में अब पार्टी कार्यकर्ताओं का खून नहीं बहेगा। सरकार को किसी भी तरह की राजनीतिक बदले की कार्रवाई पर लगाम लगानी होगी। शुभेन्दु अधिकारी को काफी प्रशासनिक अनुभव है और वह तृणमूल कांग्रेस की राजनीति के राजदार भी हैं।

सम्पादकीय...

मातृ दिवस

आज मातृ दिवस के इस पावन अवसर पर मैं संसार की प्रत्येक मां को नमन करती हूं। मां केवल एक शब्द नहीं है, मां भावना है, एक शक्ति है, एक त्याग है, एक तपस्या है। कहते हैं न जहां ईश्वर नहीं पहुंच सकते वहां मां पहुंचती है। इसलिए शायद ईश्वर ने मां को बनाया है। एक महिला कभी मां बनकर बच्चों को संस्कार देती है, कभी बहन बनकर प्रेम देती है, कभी पत्नी बनकर परिवार को सम्भालती है और कभी बेटी बनकर घर में खुशियां लाती है। समय के साथ-साथ मां सुपर वूमन भी बन जाती है।सुपर वूमन कैसी होती है, जो अपने आंसू छिपाकर परिवार को मुस्कान देती है, जो थकने के बाद भी बच्चों का भविष्य बनाती है। जो अपने सपनों के साथ-साथ परिवार के सपनों को भी पूरा करती है, वही असली सुपर वूमन होती है। मातृ दिवस सम्मान का ही नहीं बल्कि हमें मां को अवसर और सहयोग भी देना होगा। यदि एक महिला के रूप में मां का सम्मान होता है तो परिवार मजबूत होता है। परिवार मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है। जब समाज मजबूत होता तो राष्ट्र भी मजबूत होता है। मां ममता है, मां शक्ति है, मां जीवन की सच्ची भक्ति है। जिस घर में मां का सम्मान होता है तो वह घर सच्चे अर्थों में भगवान का घर है। जब घर में बैठी मां को पूजा जाता है तो उसका दर्जा देवी मां जैसा हो जाता है तथा वह प्रसन्न हो जाती है। इसलिए घर में बैठी मां को प्रसन्न रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। संस्कार, नैतिकता और नई पीढ़ी के कर्तव्य सब मां को समर्पित हैं और रहेंगे भी। मातृ दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि माँ के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। संसार में माँ का स्थान सबसे ऊँचा माना गया है। वह केवल जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रथम गुरु भी होती है। बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर और पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में «मातृ देवो भवः» कहा गया है, अर्थात् माँ को देवता के समान सम्मान देना चाहिए लेकिन यह भी सच है कि आज के आधुनिक युग में जहाँ तकनीक और भौतिकता तेजी से बढ़ रही है, वहीं पारिवारिक संस्कार और नैतिक मूल्य धीरे-धीरे कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में मातृ दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति, नैतिकता और जीवन के मूल मूल्य माँ से ही प्रारम्भ होते हैं। नई पीढ़ी को यदि संस्कारी, जिम्मेदार और नैतिक बनाना है, तो उन्हें माँ के महत्व को समझाना अत्यंत आवश्यक है। बदलते समय में आज की नई पीढ़ी सोशल मीडिया, मोबाइल और आधुनिक जीवनशैली में इतनी व्यस्त हो गई है कि परिवार के साथ समय बिताना कम हो गया है। कई बच्चे अपने माता-पिता, विशेषकर माँ के त्याग और संघर्ष को समझ नहीं पाते। वे सफलता और धन को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लेते हैं। यही कारण है कि समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई देता है। मातृ दिवस केवल उपहार देने का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन का अवसर है कि क्या हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, क्या हम उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, और क्या हम उनके संस्कारों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। हमारे इतिहास तथा भारतीय संस्कृति में मां को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है।

भाजपा को परखने के औजार बदलने होंगे

राकेश सैन ।

भारतीय जनता पार्टी की बंगाल जीत ने केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। सभी अपने-अपने मापदण्डों पर इस चुनाव परिणाम को परख रहे हैं परन्तु पुराने ढर्रों पर चलते हुए फिर से गलती पर गलती दोहराते लगते हैं। यहां के विपक्ष की मानें तो यह एसआईआर के प्रयोग से निकला विजयमार्ग है तो विदेशी विश्लेषक फिर से जिंगल बैल जिंगल बैल की तर्ज पर साम्प्रदायिकता का गीत गाने लगे हैं। इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि भाजपा ने कहीं पहली बार पांव जमाए हैं, कहीं वह फिर से सत्ता में आई है तो कहीं उसने अपना जनाधार बढ़ाया है। अगर केरल जैसे राज्य में वामपंथी दलों को भाजपा के प्रभाव के डर से अयप्पा के दर्शन करने पड़ें, भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से बंजर कहे जाने वाले बंगाल में कमल की फसल लहलहाने लगे, द्रविड़ राजनीति के केंद्र तमिलनाडु में उसकी आहट सुनने लगे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विरोधी इस दल को गलत औजारों से परख रहे हैं। विरोधी भूलते हैं कि देश का मतदाता मतिहीन नहीं है, वह सुशासन व विकास को अपनी पसंद बनाता जा रहा है। अगर कोई दल संविधान के अनुरूप काम करते हुए जनता की पसंद बन रहा है तो विरोधियों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। भाजपा केंद्र और बहुत से राज्यों में वर्षों से शासन में है। अंधविरोध के चरम पर जा कर भी शासन व संवैधानिक व्यवस्था के किसी मान्य मापदण्ड पर विपक्ष अभी तक ऐसा कोई मुद्दा तलाश नहीं पाया है जो जनता को भी मान्य हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री कई बार चुटकी ले चुके हैं कि सार्वजनिक जीवन में विपक्ष उनकी कोई तथ्यात्मक आलोचना करने में असफल रहा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता तक पहुंचते ही वैश्विक वैचारिक गलियारों में भी बेचैनी पैदा हो गई है। विदेशी मीडिया के बड़े हिस्से ने भारत में लोकतंत्र, अल्पसंख्यक अधिकार और चुनावी निष्पक्षता पर अचानक सवाल उठाने शुरू कर दिए। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन और अल जजीरा जैसे मंचों पर फिर से यह विमर्श तेजी से गढ़ा जाने लगा कि भारत हिन्दू राष्ट्रवाद की ऐसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां लोकतंत्र व बहुलता खतरे में है। विदेशी मीडिया में यादा चर्चा बंगाल की है। सवाल यही है कि क्या चिंता वास्तव में लोकतंत्र की है या उस सियासी बदलाव की, जिसने

दशकों पुराने वामपंथ और छद्मधर्मनिरपेक्षता के वैचारिक गढ़ को ध्वस्त कर दिया जब भाजपा हारती है, तो विदेशी मीडिया भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता की तारीफ करता है, पर जैसे ही वह निर्णायक जनादेश लेकर आती है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया संदिग्ध और संस्थागत संकट की भाषा में बदल जाती है। श्रेष्ठभावना से ग्रसित पश्चिमी जगत कहीं यह तो नहीं मानता कि भारतीय मतदाताओं में राजनीतिक समझ का अभाव है. राष्ट्रवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अनेक विचारक स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का राष्ट्रवाद संकीर्ण पश्चिमी राष्ट्रवाद से सर्वथा विपरीत है। पश्चिमी मीडिया भारत को अक्सर यूरोपीय राजनीतिक अनुभवों के चश्मे से देखने की कोशिश करता है। वहां राष्ट्रवाद का अर्थ सत्ता विस्तार व नस्लीय वर्चस्व रहा है। जबकि भारत में राष्ट्रवाद सांस्कृतिक, सभ्यतागत पहचान और ऐतिहासिक आत्मबोध से जुड़ा है। इसे विदेशी मीडिया समझ नहीं पाता। इसीलिए वो हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को सीधे अल्पसंख्यक-बहुसंख्यकवाद से जोड़ देता है। यही कारण है कि बंगाल में भाजपा की जीत को पश्चिम के विश्लेषकों ने लोकतांत्रिक परिवर्तन के बजाय हिंदू राष्ट्रवादी कब्जे की तरह प्रस्तुत किया गया। एसआईआर पर अधिसत्य दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिणामों के बाद वोट चोरी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भाजपा का आयोग बताया। विदेशी मीडिया ने इन आरोपों को लगभग बिना तथ्य जांचे ही अपने विमर्श का आधार बना लिया। विशेष रूप से एसआईआर को मुस्लिम मतदाताओं को हटाने की साजिश के रूप में पेश किया गया, जबकि हटाए गए 91 लाख नामों में 63 प्रतिशत हिंदू मतदाता थे। बड़ी संख्या में नाम मृत, डुप्लिकेट, स्थायी रूप से स्थानांतरित या फर्जी पाए गए थे।

इसके बावजूद विदेशी मीडिया के बड़े हिस्से ने केवल मुस्लिम वोट हटाए गए वाली जिद को प्रमुखता दी। देसी-विदेशी विश्लेषक यह भूल गए कि जिन 20 सीटों पर जांच के बाद सबसे यादा वोट काटे गए थे, उनमें से यादातर पर टीएमसी ने ही कब्जा जमाया है। इन सीटों में समशेरगंज, लालगोला, भगवानगोला, रघुनाथगंज, मटियाबुर्ज, सूती, मोथाबाड़ी, गोलपोखर, मालतीपुर, चोपड़ा, सुजापुर, राजारहाट न्यू टाउन और बशीरहाट उत्तर शामिल हैं। इन सभी 13 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी को जीत मिली है। अन्य सीटों की बात करें तो फरक्का सीट पर सबसे यादा 38,222 वोट काटे गए थे, लेकिन वहीं से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं भाजपा को जगीपुर, सुआ, करनदिघी, केतुग्राम, मानिकचक और मोतिबार जैसी 6 सीटों पर जीत मिली। यह अकेला आँकड़ा ही उस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल देता है जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि वोटर लिस्ट में सुधार से सिर्फ टीएमसी को नुकसान हुआ और भाजपा को फायदा पहुँचा। अगर बड़े पैमाने पर देखें, तो जिन 187 सीटों पर 5,000 से यादा वोटर्स के नाम काटे गए थे, वहां भाजपा ने 119 और टीएमसी ने 65 सीटों पर जीत दर्ज की। इन 187 सीटों में से 47 सीटें ऐसी थीं, जहाँ कटे हुए वोटों की संख्या जीत के अंतर से यादा थी। भाजपा ने जो 119 सीटें जीतीं, उनमें से 28 सीटों पर जीत का अंतर कटे हुए वोटों से कम था। इन आँकड़ों से साफ है कि कई सीटों पर कांटे की टक्कर थी और वहाँ कटे हुए वोटों की संख्या जीत के मार्जिन से यादा रही। लेकिन हार का पूरा ठीकरा सिर्फ वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया पर फोड़ देना और इसे ही हार की एकमात्र वजह बताना पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। सच्चाई यह है कि देसी-विदेशी विश्लेषकों को नरेंद्र मोदी और भाजपा का बढ़ता राजनीतिक विस्तार विदेशी वैचारिक प्रतिष्ठानों की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका है। खास कर उन क्षेत्रों में यह जलन यादा है जो 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस को मिली थोड़ी राजनीतिक राहत को लेकर उत्साहित चला आरहा था। आज भाजपा अधिकांश राज्यों में प्रत्यक्ष या गठबंधन के जरिए सत्ता में है। ऐसे में भारत को हिन्दू राष्ट्रवादी लोकतंत्र और एकदलीय प्रभुत्व के खांचे में फिट करने की कोशिशें और तेज होती दिख रही हैं। परंतु बंगाल का फैसला यह भी साबित करता है कि भारत का मतदाता अपनी प्राथमिकताएं जमीन, अनुभव और आकांक्षाओं के आधार पर तय कर रहा है, न कि न्यूयॉर्क, लंदन या दोहा में बैठे नैरेटिव निर्माताओं की वैचारिक दृष्टि के अनुसार। विदेशी विश्लेषणों में बंगाल के चुनावी परिणाम को हिन्दुत्व के उभार के रंग में रंग दिया।

लेकिन वहां की जनता की नाराजगी, आर्थिक बदहाली, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, सत्ताधारियों की हिंसा, उद्योगों का पलायन जैसे कारणों की अनदेखी कर गया। आज बंगाल पर कर्ज 7.7 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है। हजारों कंपनियां राज्य छोड़ चुकी हैं। युवाओं का बड़ा वर्ग रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। महानगरों में घरों में काम करने वाली अधिकतर महिलाएं बंगाली ही निकलती हैं। कट मनी, भर्ती घोटाले और सिंडिकेट संस्कृति जैसे मुद्दे वर्षों से जनता में असंतोष पैदा कर रहे थे। लेकिन देसी-विदेशी विश्लेषक उलझे हैं एसआईआर और बहुसंख्यकवाद के उभार में। इसी दकियानूसी सोच के आधार पर यह तत्व जनता में अप्रासंगिक हो रहे हैं और भाजपा का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है।

नव-फ़ासीवाद का उभार, बीजेपी और शिक्षा

प्रभात पटनायक

बहुत से विचारवान लोग यह मानते हैं कि निरुपनिवेशीकरण के बाद भी लंबे अर्से तक भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में एक छोटे से अंग्रेजीभाषी अभिजात तबके का जो बोलबाला बना रहा था, वह उस देसी भाषा-भाषी नवोदित अभिजात तबके का शत्रुभाव भड़कने का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो बहिष्कृत महसूस करता रहा था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर खिंच गया है। दूसरे शब्दों में यह कि भाजपा अन्य चीजों के अलावा देश के मामलों में छोटे से अंग्रेजीभाषी अभिजात वर्ग के बोलबाले के खिलाफ एक प्रकार के विद्रोह को प्रदर्शित करती है। इसमें सचाई का कुछ अंश हो भी सकता है और बहस के लिए हम फिलहाल यह मान लेते हैं कि यह नजरिया सही है। लेकिन, इसका अर्थ तो यह है कि उन्हें शिक्षा के जनतांत्रीकरण के जरिए और खासतौर पर उच्च शिक्षा के जनतांत्रीकरण के जरिए, इस छोटे से अंग्रेजीभाषी अभिजात तबके के बोलबाले को तोड़ने का प्रयास करते रहा होना चाहिए, जिससे समय गुजरने के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा इतने सारे लोगों को उपलब्ध हो जाती कि जो विशेषाधिकार अब तक छोटे से अभिजात वर्ग को मिल रहे थे, वे विलुप्त ही हो जाते। किसी को भी लगेगा कि भाजपा जो बहुतेरों के बहिष्करण के इस एहसास भुनाती आयी है, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का जनतांत्रीकरण कर रही होगी और उसे अब तक उच्च शिक्षा से बहिष्कृत छात्रों के निरंतर बढ़ते कुल की पहुंच में ला रही होगी और मुट्ठीभर प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं की इजारेदारी (एकाधिकार) को तोड़ रही होगी, जो संस्थाएं अपने यहां शिक्षितों की संतानों को विशेषाधिकारपूर्ण पहुंच मुहैया कराने के जरिए, एक छोटे से अभिजात तबके के खुद को संरक्षित रखने की प्रक्रिया में औजारों का काम करती हैं। ठीक इसी के लिए वह कहीं बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थाएं शुरू कर रही होगी। बहरहाल, भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार, ठीक यही तो नहीं कर रही है। उसका ध्यान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जनतांत्रीकरण पर न होकर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विनाश पर है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसी जो चंद गुणवत्तापूर्ण ऐसी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो अपनी समावेशी दाखिला नीति के चलते, अभिजात तबके के बच्चों से कहीं यादा, आबादी के बृहत्तर हिस्से के बच्चों को शिक्षित करती आ रही थीं, लेकिन उन्हें तो व्यवस्थित तरीके से नष्ट ही करने की कोशिशें की जाती रही हैं। उच्च शिक्षा के जनतांत्रीकरण के उक्त एजेंडा के तकाजों को पूरा करने के लिए, शिक्षा पर बहुत बढ़ी हुई मात्रा में खर्च करने के बजाए, यह सरकार तो अपने शिक्षा बजट में भारी कटौतियां ही करती आयी है। इसका लक्ष्य तो उच्च शिक्षा का निजीकरण करना ही रहा है और यह उच्च शिक्षा को इतना महंगा बना देता है कि गैर-अभिजात पृष्ठभूमि के बच्चों की हैसियत ही नहीं होती है कि इन नयी निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं में पांव रख सकें। जहां पहले चंद प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान थे जो अभिजात तबका पैदा करते थे, उनकी जगह अब कुछ और प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हो गए हैं और ये संस्थान भी अभिजात तबके को ही पैदा करने में लगे हुए हैं, हालांकि जरा भिन्न किस्म के अभिजात तबके को और काफी सचेत रूप से ऐसा करने का लक्ष्य बनाकर यह कर रहे हैं। बहिष्करण की यह प्रक्रिया, जिसके विरोध ने भाजपा को कथित रूप से बहुतों के लिए आकर्षक बनाया था, और भी जोर-शोर से जारी है। वास्तव में आज तो यह प्रक्रिया, आजादी के फौरन बाद के वर्षों में जिस गति से जारी थी, उससे भी तेज गति से जारी है। जहां शिक्षा के जनतांत्रीकरण के एजेंडा को इस तरह धता बता दी गयी है, वहीं सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं को पैसे के लिए तरसाया जा रहा है (जिसमें वर्षों तक उन्हें बहुत ही अपर्याप्त स्टाफ से काम चलाने पर मजबूर करना शामिल है, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वहां कोई खास पढ़ना-पढ़ाना ही नहीं हो), शिक्षकों को अपने विषयों में उनकी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि हिंदुत्व के एजेंडा के प्रति उनकी घोषित वफादारी के आधार पर भर्ती किया जा रहा है और बिना किसी अकादमिक औचित्य के पाठ्यक्रम से विषय के बड़े-बड़े हिस्सों को हटाया जा रहा है (जैसे अनेक स्कूलों में इतिहास की पढ़ाई में से मुगल काल का हटाया जाना)। यह सब यही सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं का अकादमिक स्तर बहुत ही नीचे चला जाए। चूंकि निजी शिक्षा संस्थाओं का ध्यान और इसमें ऐसी सबसे प्रतिष्ठित तथा सबसे महंगी शिक्षा संस्थाएं भी शामिल हैं, मुख्यत रोजगार के बाजार की जरूरतें पूरी करने पर केंद्रित रहता है, न कि छात्रों को आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य के साथ ज्ञान देने पर, व्यावहारिक रूप से हो यह रहा है कि आलोचनात्मक चिंतन को ही नष्ट किया जा रहा है और इसका अर्थ होता है, बुनियादी तौर पर शिक्षा का ही विनाश। अब सवाल यह है कि एक ऐसी सरकार, जो छोटे से अंग्रेजी बोलेने वाले अभिजात वर्ग के विरोध की कसमें खाती है और इस तरह के विरोध के आधार पर हमदर्दी हासिल करती है, शिक्षा का जनतांत्रीकरण करने के बजाए उसका विनाश ही करने में क्यों लगी हुई है इस सवाल का जवाब हमें नव-फासीवाद की एक बुनियादी विशेषता में मिलेगा। और वह विशेषता यह है कि नव-फासीवाद अक्सर विशेषाधिकारों का विरोध करने के नाम पर लोगों को लुभाता जरूर है, लेकिन यह असल में समाज के सबसे विशेषाधिकार -प्राप्त समूह, इजारेदार पूंजीपतियों के ही एजेंडा को लागू करता है। दूसरे शब्दों में फासीवाद और नव-फासीवाद की इमारत, एक बुनियादी छल पर ही खड़ी की जाती है। मिसाल के तौर पर 1930 के दशक का जर्मन फासीवाद खुद को ''नेशनल सोशलिज्म'' बताता था। वह बड़ी पूंजी के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करता था, जबकि चोरी-छिपे उसके साथ रिश्ते बनाए हुए था। और जब वह सत्ता में आ गया और उसने बड़ी पूंजी के साथ खुल्लमखुल्ला रिश्ते कायम कर लिए, उसने अपने उन अनुयाइयों का सफाया ही कर दिया, जो उसकी पहले वाली लफ्फाजी में आ गए थे और उसके पहले वाले दावों से ही चिपके रहे थे। खून-खराबे भरे सफाए में उनका खात्मा ही कर दिया गया, जिसे इतिहास में 'लंबे चाकुओं वाली रात' के नाम से दर्ज किया गया था। इसी तरह की बेईमानी, आज हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में चल रही है। नव-फासीवादी तत्वों का प्रभाव, उनके इस अंतर्निहित वादे से आता है वे शिक्षा के जनतांत्रीकरण के एजेंडा को लागू करेंगे। लेकिन, इजारेदार पूंजी शिक्षा के विनाश का तकाजा करती है। इसलिए, उनका असली एजेंडा शिक्षा का विनाश करना हो जाता है। लेकिन, इससे आगे यह सवाल उठता है कि इजारेदार पूंजी को शिक्षा का विनाश क्यों चाहिए और किस अर्थ में आज शिक्षा को नष्ट किया जा रहा है। शिक्षा के इस तरह के विनाश का अर्थ इस प्रकार है। तकनीकी ज्ञान तथा कौशल का तो जोर-शोर से प्रसार किया जा रहा है। लेकिन, समाज के संबंध में तमाम ज्ञान से या यथास्थिति की अनालोचनात्मक सराहना को छोड़कर और किसी भी रूप में समाज की गतिकी पर हलके सोच-विचार से, पूरी तरह से परहेज किया जाता है। वर्तमान की किसी भी आलोचनात्मक पड़ताल के साथ तो बहुत ही हिकारत के साथ पेश आया जाता है। इजारेदार पूंजी को कुशल मजदूरों की जरूरत होती है और इन्हें इन नयी उभरती हुई निजी संस्थाओं से पैदा करने की अपेक्षा की जाती है और वे पैदा करती भी हैं। लेकिन, समाज के किसी भी अध्ययन को, जो अनिवार्यत आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य से करना होता है, इजारेदार पूंजी खतरनाक मानती है और इस तरह के अध्ययन को पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया जाता है। जाने-माने मार्क्सवादी अर्थशास्त्री, पॉल बरान ने एक मौके पर ''बुद्धिजीवियों'' और ''बौद्धिक कार्मिकों'' के बीच अंतर किया था। हम अपने तर्क को इस अंतर के माध्यम से रख सकते हैं। इजारेदार पूंजी के वर्चस्व के दौर में उच्च शिक्षा संस्थाएं, बजाए ''बुद्धिजीवी'' पैदा करने के, जो जनता के हितों की सेवा करें और उसे अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, ''बौद्धिक कार्मिक'' पैदा करती हैं, जो इजारेदार पूंजी की (और बहुराष्ट्रीय निगमों की, जिनके साथ घरेलू इजारेदार पूंजी गठबंधन करती है) सेवा करती हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने कनक ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ [illegible] एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

राप्ती नदी के प्रवाह को निर्मल बनाने में जुटी योगी सरकार

मानसून से पहले पूरी हो जाएगी महेवा नाला इंटरसेप्शन, डायवर्जन, ट्रीटमेंट परियोजना
53 करोड़ रुपये की परियोजना में कराया जा चुका 96 प्रतिशत से अधिक कार्य
10 एमएलडी की एसटीपी से राप्ती नदी में गिरने वाले कचरे को किया जा सकेगा नियंत्रित

गोरखपुर।

राप्ती नदी के प्रवाह को निर्मल बनाने में जुटी योगी सरकार, इस बार मानसून शुरू होने के पहले नदी में गिरने वाले कचरे के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित और शोधित करने की परियोजना को पूर्ण करा लेगी। शहर के उत्तरी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण महेवा/कटनिया नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन व ट्रीटमेंट की परियोजना में 96 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है और इसी माह के अंत तक इसके पूरी तरह पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा राप्ती नदी की धारा को अविरल बनाने की है। इसके लिए जहां तकियाघाट से होकर नदी में गिरने वाले नाले पर बायो रेमेडिएशन विधि से जल शोधन का कार्य हो रहा है तो वहीं महेवा/कटनिया नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन और ट्रीटमेंट की 53 करोड़ रुपये की परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्षों से शहर का सीवेज महेवा, कटनिया जैसे बड़े नालों के जरिये सीधे राप्ती नदी में मिलता रहा। अब नदी में मिलने वाले नालों को इंटरसेप्ट, डायवर्ट करने के साथ ही नालों के जल का ट्रीटमेंट किया जाएगा। महेवा, कटनिया नाला महेवा, रुस्तमपुर एवं महुईसुधरपुर वार्ड के नागरिकों द्वारा उपभोग किए जल और सीवेज को नदी में उड़ेलता है। अब इस नाले के पानी को नदी में गिरने से पहले ही रोका जाएगा और पाइपलाइनों के जरिए एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) तक डायवर्ट किया जाएगा।

डायवर्ट किए पानी व सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय की तरफ से 10 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 27 एमएलडी क्षमता के मास्टर पम्पिंग स्टेशन (एमपीएस) का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे पानी के शोधित होने के बाद ही नदी में डिस्चार्ज किया जाएगा। मानसून से पहले इस परियोजना के क्रियाशील होने पर बारिश के मौसम में नदी में जाने वाले अतिरिक्त कचरे को नियंत्रित किया जा सकेगा। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार बताते हैं कि महेवा/कटनिया नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन व ट्रीटमेंट की परियोजना पर काम 29 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। अब तक 96 प्रतिशत से अधिक कार्य कराया जा चुका है। अब अंतिम दौर के और कुछ फिनिशिंग के काम शेष हैं।

रोटरी क्लब कुशीनगर ने मातृ दिवस पर बांटी हाइजीन किट, माताओं और नवजातों के स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक

कसया, कुशीनगर।

अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब कुशीनगर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसया में नवजात शिशुओं की माताओं को हाइजीन किट वितरित कर मातृ दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. मुकेश यादव ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सुरक्षा समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और समय पर देखभाल से कई गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है तथा ऐसे सामाजिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉ. नेहा पाठक ने कहा कि नवजात शिशुओं और माताओं की देखभाल में स्वच्छता का विशेष महत्व है। उन्होंने रोटरी क्लब कुशीनगर द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल माताओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को दर्शाती है। इस अवसर पर क्लब के सह संरक्षक वाहिद अली ने कहा कि माताएं समाज की आधारशिला होती हैं और उनके सम्मान एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब सदैव समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।

वहीं क्लब के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि मातृ दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि माताओं के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि क्लब भविष्य में भी स्वास्थ्य एवं जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष दिनेश यादव, उपाध्यक्ष विजय कृष्ण द्विवेदी, उपाध्यक्ष दुर्गेश चतुर्वेदी, सोशल मीडिया प्रभारी सुनील सिंह, अमित श्रीवास्तव, अखिलेश शर्मा, सत्येन्द्र राय, हसमुद्दीन अंसारी एवं आदिल खान सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

पप्पू पांडेय ने की अपील - जनगणना में सही पहचान दर्ज कारण मुसहर समाज

कुशीनगर।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रविवार को जनपद के जंगल विशुनपुरा में एक बृहद चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता पप्पू पांडेय रहे, जबकि संचालन भाजपा मंडल मंत्री मनोज कुमार गोंड ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए पप्पू पांडेय ने कहा कि आगामी जनगणना 2026-27 मुसहर समाज के उत्थान के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग जागरूक बनें और जनगणना के दौरान अपनी सही पहचान दर्ज कराएं, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गाँव-गाँव जाकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनगणना संगणकों द्वारा 22 मई से घर-घर जाकर गणना की जाएगी, जबकि 7 मई से 21 मई तक स्व-गणना का कार्य परिवार के मुखिया द्वारा किया जाना है। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि गणना के समय कॉलम नंबर 13 पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही कॉलम समाज की सही पहचान सुनिश्चित करेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि गणना अधिकारी द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज बिना किसी भय के उपलब्ध कराएं और जनगणना कार्य में पूरा सहयोग करें। कार्यक्रम में शकरीम, अमर, लक्ष्मण, धर्मेंद्र, जगदेव, रामस्वरूप, कैलाश, नारायण, गोपी, मुन्ना, संजय, चन्द्रशेखर, शंकर, रामायण सहित सैकड़ों मुसहर परिवार उपस्थित रहे।

गोरखपुर लोक अदालत ने सुलझाए 12 लाख से यादा मामले, बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड

गोरखपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं नोडल अधिकारी नीरज श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक रूप से 12 लाख आठ हजार 888 मामले निस्तारित कर जिले ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सभी न्यायालयों द्वारा कुल एक हजार 720 आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।

लोक अदालत में कुल 12 लाख 39 हजार 592 मामले नियत किए गए थे। इनमें से 12 लाख आठ हजार 888 मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया।प्राधिकरण के सचिव प्रतिभा चौधरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने नई मीटिंग हाल में सुबह 10:30 बजे मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रवलित कर किया। लोक अदालत में अपर जिलाधिकारी प्रशासन / नोडल अधिकारी, उपजिलाधिकारियों सहित अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता की गई। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह द्वारा दो वादों का निस्तारण किया गया। पीठासीन अधिकारी वाणियिक न्यायालय द्वारा तीन वादों का निस्तारण किया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 19 वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी राजेश पति त्रिपाठी द्वारा कुल 178 वादों का निस्तारण करते हुए 10 करोड़ 16 लाख 47 हजार 367 रुपए का प्रतिकर अवार्ड पारित किया गया ।राजस्व व अन्य विभागों द्वारा कुल 11 लाख 71 हजार 967 प्री - लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक वादों से संबंधित प्री - लिटिगेशन स्तर व लिटिगेशन स्तर पर कुल 21 वादों का निस्तारण किया गया। प्री - लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों व फाइनेंस कंपनियों से संबंधित कुल एक हजार 73 मामलों का निस्तारण कर पांच करोड़ एक लाख 36 हजार 834 रुपए नकद जमा कराया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने पीएचसी खुखुन्दू पहुंचे डीएम, मरीजों से संवाद कर परखी दवाओं की उपलब्धता

समयबद्ध उपचार और कर्मचारियों की उपस्थिति पर दिया जोर, लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त हिदायत

देवरिया।

जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और जन-केंद्रित बनाने के संकल्प के साथ जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की सक्रियता निरंतर जारी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुखुन्दू (भलुअनी) का औचक निरीक्षण कर वहां की चिकित्सा व्यवस्थाओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया। जिलाधिकारी का यह दौरा केवल औपचारिक अवलोकन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक सजग प्रशासक की भांति ओपीडी से लेकर दवा वितरण काउंटर तक की कार्यप्रणाली को बारीकी से परखा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिल रहे उपचार, चिकित्सकों के व्यवहार और दवाओं की उपलब्धता के संबंध में फीडबैक लिया। जिलाधिकारी ने मौजूद चिकित्सा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि किसी भी मरीज को बाहर की दवाएं न लिखी जाएं और अस्पताल में उपलब्ध स्टॉक का शत-प्रतिशत लाभ पीड़ितों को मिले। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एक संवेदनशील सेवा है, जिसमें समयबद्धता का विशेष महत्व है; अतः सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ निर्धारित रोस्टर के अनुरूप अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

परिसर की स्वच्छता और व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य केंद्र को पूरी तरह से पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों को अनावश्यक भटकना न पड़े। उन्होंने दवा वितरण कक्ष और ओपीडी के संचालन में पारदर्शिता बरतने तथा महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधियों का बफर स्टॉक बनाए रखने को कहा। जिलाधिकारी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनहित से जुड़ी सेवाओं में किसी भी स्तर पर शिथिलता अक्षम्य होगी। नवागत जिलाधिकारी के इस निरंतर निरीक्षण अभियान ने जनपद के स्वास्थ्य महकमे में जवाबदेही की एक नई संस्कृति का संचार किया है, जिससे आमजन में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भरोसा बढ़ता दिख रहा है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्रालय को लिखा पत्र, बोले-ईआई प्रक्रिया मजाक बनी

(वेबवार्ता)

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखकर कहा कि सरकार जिस मजबूत और व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी ईआईए का दावा कर रही है, वह दस्तावेजों और रिपोर्टों में कहीं दिखाई नहीं देता। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इस परियोजना के लिए किए गए पर्यावरणीय अध्ययन बेहद सीमित, अधूरे और वैज्ञानिक मानकों के खिलाफ हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि 1 मई को सरकार ने ग्रेट निकोबार परियोजना- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी कर दावा किया था कि परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का व्यापक अध्ययन किया गया है और उन्हें प्रभावी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने 3 मई को इन पूछे जाने वाले प्रश्न का जवाब दिया था, लेकिन अब वे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखना चाहते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि कानून के मुताबिक अंडमान-निकोबार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बनने वाले बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए व्यापक ईआईए जरूरी होता है। इसके तहत कम से कम तीन मौसमों का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण और जैव विविधता पर पड़ने वाले असर का सही आकलन हो सके। उन्होंने 3 नवंबर 2009 के पर्यावरण मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला देते हुए कहा कि 50 लाख टन प्रति वर्ष से बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए व्यापक ईआईए, गणितीय मॉडलिंग और जमीनी सत्यापन अनिवार्य है। जयराम रमेश ने कहा कि मंत्रालय की क्षेत्र-विशिष्ट ईआईए नियमावली भी कम से कम दो मौसमों के भौतिक, रासायनिक और जैविक आधारभूत डेटा की मांग करती है। उन्होंने दावा किया कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में इन मानकों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इसरो की 2021 मैपिंग में गलाथिया बे के बड़े हिस्से को इरोजन जोन बताया गया था। ऐसे में तटीय विनियमन क्षेत्र नियमों के तहत और ज्यादा विस्तृत अध्ययन जरूरी था। जयराम रमेश ने दावा किया कि ग्रेट निकोबार परियोजना की फाइनल ईआईए रिपोर्ट खुद यह स्वीकार करती है कि आधारभूत अध्ययन

सिर्फ दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक यानी केवल एक मौसम में की गई थीं। उन्होंने कहा कि परिस्थितिकी और जैव विविधता का क्विक सर्वे सिर्फ 14 से 22 दिसंबर 2020 के बीच हुआ, जबकि लेदरबैक कछुओं का सर्वेक्षण केवल 12 से 18 फरवरी 2021 तक चला। उन्होंने कहा कि ईआईए रिपोर्ट में खुद माना गया है कि घने जंगलों की वजह से गहन सर्वेक्षण संभव नहीं हो सका और कई हिस्सों का अध्ययन बेहद सीमित रहा। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि जंगलों में जो अभी तक सामने नहीं आया, वह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। जयराम रमेश ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि ये अध्ययन भी कुछ दिनों या हफ्तों तक सीमित त्वरित मूल्यांकन थे। उन्होंने कहा कि एएनआईआईडीसीओ द्वारा जमा आवेदन पत्र में भी स्थलीय और समुद्री ईआईए अध्ययन की अवधि बेहद कम दिखाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन अधूरे अध्ययनों के आधार पर पर्यावरण मंजूरी देना विज्ञान का अपमान और ईआईए प्रक्रिया का मजाक है। उन्होंने कहा कि वे अब तक सरकार द्वारा दावा किए गए मजबूत ईआईए और ईएमपी को ढूंढ नहीं पाए हैं। जयराम रमेश ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के 3 अप्रैल 2023 के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें पर्यावरण मंजूरी में अनुत्तरित कमियों की बात कही गई थी और उच्च-स्तरीय समिति (एचपीसी) गठित करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूरा पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया सार्वजनिक थी, तो फिर एचपीसी रिपोर्ट को गोपनीय क्यों रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार का एचपीसी रिपोर्ट को गोपनीय बताना पारदर्शिता और जवाबदेही के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि अच्छी शासन व्यवस्था और सार्वजनिक बहस के हित में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। पत्र में जयराम रमेश ने कहा कि ग्रेट निकोबार की जैव विविधता दुनिया में अनोखी है और यह परियोजना इस पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने क्षतिपूरक वनीकरण के तर्क को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि कई सुरक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा जरूरतें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी की जा सकती हैं। उन्होंने सरकार से इस परियोजना के मौजूदा डिजाइन और

सेंट्रल रिज के 673 हेक्टेयर को मिला आरक्षित वन का दर्जा, देसी वृक्षों से बढ़ेगी जैव विविधता

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सेंट्रल रिज के 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है। इससे राजधानी में हरियाली बढ़ेगी, प्रदूषण पर लगाम लगेगी और जैव विविधता को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेंट्रल रिज के करीब 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित किया है। ये इलाका वन विभाग के पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आता है और सरदार पटेल मार्ग व राष्ट्रपति भवन एस्टेट के आसपास फैला हुआ है। सरकार ने कहा कि इस फैसले से दिल्ली के पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि रिज क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा देने का मुद्दा कई दशकों से लंबित था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। इससे न सिर्फ हरित क्षेत्र बढ़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित होगा। सेंट्रल रिज राजधानी के लिए ग्रीन लंग्स - मुख्यमंत्री कहा कि सेंट्रल रिज राजधानी के बीचोंबीच स्थित है और इसे दिल्ली के 'ग्रीन लंग्स' के रूप में जाना जाता है। ये इलाका हवा की गुणवत्ता

सुधारने, भूजल स्तर बनाए रखने और शहरी प्रदूषण के असर को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। रिज दरअसल प्राचीन अरावली पर्वतमाला का ही विस्तार है, जो प्राकृतिक रूप से शहर को संतुलित रखने में मदद करता है।

केवल देसी और पर्यावरण के अनुकूल पौधे लगाए जाएंगे

सरकार ने ये भी साफ किया कि आरक्षित वन घोषित किए क्षेत्रों में जहां भी खाली और उपयुक्त जमीन उपलब्ध होगी, वहां बड़े पैमाने पर देसी और पर्यावरण के अनुकूल पौधे लगाए जाएंगे। इनमें नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसे फलदार पेड़ भी शामिल होंगे। इस पहल का मकसद सिर्फ हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे इलाके की पारिस्थितिकी को मजबूत करना है।

लंबित थी ये प्रक्रिया

मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह प्रक्रिया काफी समय से लंबित थी। वर्ष 1994 में दिल्ली के सभी पांच रिज क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन उन्हें अंतिम कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाया था। अब सेंट्रल रिज को आरक्षित वन घोषित करने के साथ यह लंबा इंतजार खत्म हुआ है।

इससे पहले 4080.82 हेक्टेयर क्षेत्र रिजर्व घोषित

इससे पहले पिछले साल 24 अक्टूबर को दक्षिणी रिज के करीब 4080.82 हेक्टेयर क्षेत्र को भी आरक्षित वन घोषित किया गया था। सेंट्रल रिज की नई अधिसूचना के बाद अब तक कुल 4754.14 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को यह दर्जा मिल चुका है। सरकार का कहना है कि बाकी रिज क्षेत्रों को भी जल्द ही इसी तरह आरक्षित वन घोषित किया जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

वन क्षेत्र को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिली

आरक्षित वन का दर्जा मिलने के बाद अब इन इलाकों को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इससे अतिक्रमण, अवैध निर्माण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही वन विभाग को संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन के कामों को और बेहतर तरीके से लागू करने का मौका मिलेगा।

प्रदूषण के खिलाफ भविष्य के लिए योजना

सरकार का मानना है कि ये कदम सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी है। बढ़ते प्रदूषण और तेजी से फैलते शहरीकरण के बीच ऐसे फैसले ही शहर को सांस लेने लायक बनाए रख सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण को लेकर गंभीर है और दिल्ली की हरित संपदा को बचाने के

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला- सिर्फ कर्ज न चुकाने पर जारी नहीं हो सकता लुक आउट सर्कुलर

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कर्ज न चुकाने के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एलओसी एक अंतिम कार्रवाई के रूप में की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही है और बैंक ऋण अदा करने में चूक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिए गए ऋण के हर मामले में एलओसी जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जहां एलओसी जारी करने वाले व्यक्ति को गबन या हेराफेरी के किसी अपराध में आरोपित नहीं बनाया गया है, वहां एलओसी मान्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही पीठ ने अलग-अलग मामलों में वित्तीय संस्थानों, बैंकों व जांच एजेंसियों के अनुरोध पर 23 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए एलओसी को रद कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कोर्ट की पहले से अनुमति लिए बिना विदेश यात्रा करने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें अपनी रवानगी से कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित विभाग या एजेंसी को इसकी सूचना व अपना यात्रा का पूरा ब्योरा देना होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून में किसी बदलाव या कोर्ट के आदेश सहित किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के तहत जांच एजेंसी एलओसी जारी करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगी। सभी याचिकाकर्ता को राहत देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि एलओसी की जरूरत, उसकी कानूनी वैधता को सही ठहराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसे जारी करने वाली एजेंसी की होती है। पीठ ने कहा कि एलओसी अनिश्चित काल के लिए जारी नहीं किया जा सकता और इसकी समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए, ताकि जब इसका मकसद पूरा हो जाए, तो इसे वापस ले लेना चाहिए। पीठ ने कहा कि एलओसी जारी करने वाले अधिकारी को जांच एजेंसी के हथियार के तौर पर काम नहीं करने के बजाय ठोस और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए। विभिन्न मामलों में फंसे 23 लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआइ, एसएफआइओ व विभिन्न बैंकों के कहने पर एलओसी जारी किया गया था। इन सभी ने एलओसी को चुनौती दी है। अदालत ने 23 याचिकाओं को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। इसमें ए श्रेणी में कुछ मामले ऐसे थे जिसमें केवल वित्तीय संस्थानों के अनुरोध पर एलओसी जारी किया गया था, जबकि बी श्रेणी में जांच एजेंसियों के अनुरोध पर एलओसी जारी किया था। वहीं, सी श्रेणी में याचिकाकर्ता को एलओसी जारी करने वाले फोरम के पास भेज दिया गया था। प्रत्येक श्रेणी कुछ अलग, लेकिन आपस में जुड़े हुए कानूनी मुद्दे को उठाती है और सभी का समाधान इस निर्णय में उचित क्रम में

77 तालाबों का 90 दिनों में होगा कायाकल्प, तीन चरणों में पूरा होगा जलाशयों को जीवन देने का मास्टर प्लान

नई दिल्ली। गहराते जल संकट को देखते हुए सूख रहे 77 जलाशयों (तालाबों और झीलों) का कायाकल्प होगा। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए को इसे मिशन मोड में काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने प्राधिकरण को चेतावनी दी है कि अगले 90 दिनों के भीतर इन जलाशयों की सूरत बदल जानी चाहिए। अधिकारियों के साथ शनिवार को समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि रख-रखाव की कमी और अवैध कब्जों के कारण दिल्ली की जलीय संपत्तियां तेजी से खत्म हो रही हैं। एलजी ने निर्देश दिए कि इन जलीय संपत्तियों को बचाने के लिए तुरंत ठोस योजना जमीन पर उतारी जाए, ताकि बारिश के पानी को बर्बाद होने से रोका जा सके। प्रशासन ने इन 77 जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए समय सीमा तय की है, जिसे सख्ती से लागू किया जाएगा। अगले 30 दिन सबसे पहले उन 6 जलाशयों पर काम होगा, जिनमें केवल सफाई और खुदाई की जरूरत है। 60 दिनों के भीतर 48 छोटे जलाशयों का कायाकल्प किया जाएगा, जहां गंदगी हटाकर गहराई बढ़ाई जाएगी। 90 दिनों के भीतर 23 बड़े जलाशयों को पूरी तरह से ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला चरण सफाई और खुदाई से जुड़ा होगा। सबसे पहले जलाशयों की गहराई में जमी कीचड़ और गंदगी को मशीनों से बाहर निकाला जाएगा। इसके आसपास के उन रास्तों को भी साफ किया जाएगा जहां से बारिश का पानी बहकर तालाब में आता है। इसका मकसद बारिश का ज्यादा पानी तालाबों में इकट्ठा हो सके। दूसरा चरण सौंदर्यीकरण और सुरक्षा का होगा, जब तालाबों में पानी रुकने लगेगा तब उनके किनारों को मजबूत किया जाएगा। तालाब के चारों ओर बाड़ लगाई जाएगी, पेड़-पौधे रोपे जाएंगे और यदि पानी को साफ करने के लिए छोटे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि पानी स्वच्छ रहे। उपराज्यपाल ने कहा कि ये झीलें और तालाब दिल्ली के पर्यावरण के लिए अनमोल हैं। इस योजना से आम लोगों को सीधा लाभ होगा, भूजल स्तर में सुधार होगा।

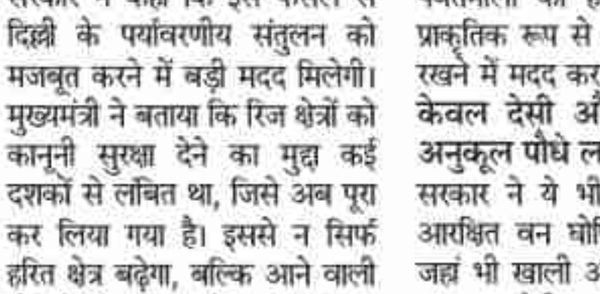

तालाबों में पानी भरने से जमीन के नीचे का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे बोरवेल और हैंडपंपों में पानी की कमी दूर होगी।

दिल्ली-एनसीआर में दो दिन बारिश- आज से सक्रिय होगा विक्षोभ, आज आंधी-बारिश के आसार

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वीकेंड गर्म रहने के बाद अगले सप्ताह से मौसम का मिजाज फिर बदलने जा रहा है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से ना केवल धूल भरी हवाएं चलेंगी बल्कि बारिश होने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने 11 व 12 मई को आंधी व बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इस कारण से अगले सप्ताह तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। 17 मई तक तापमान 40 डिग्री से नीचे ही बना रहेगा और लू चलने की भी संभावना नहीं है। इससे जेठ वाली गर्मी का अहसास अभी नहीं होगा।

मौसम विभाग के अनुसार 10 मई को पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस कारण से 11 व 12 मई को 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश होने का भी अनुमान जताया गया है। 13 मई को भी दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं शनिवार को आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली। इस कारण से अन्य दिनों के मुकाबले में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि यह सामान्य तापमान से कम ही दर्ज हुआ। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य 2.9 डिग्री कम 36.9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री कम 35.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में सामान्य से 2.2 डिग्री कम 35.8, रिज में सामान्य से 3.1 डिग्री कम 36.2 और आयानगर में सामान्य से 4 डिग्री कम 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया था। लेकिन पूरे दिन धूप निकली रही इससे हल्की गर्मी का अहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई को अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री के बीच रहने व 11 व-12 मई को 35-39 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 13 से 14 मई को तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच दर्ज होने की संभावना है।

मिर्गी मरीजों को बड़ी राहत: दिल्ली एम्स में महंगे टेस्ट होंगे फ्री, मिलेंगी कई नई सुविधाएं

नई दिल्ली। मिर्गी के मरीजों की महंगी जांच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स) में अब निशुल्क होगी। एम्स ने स्पष्ट किया है कि यह जांच सुविधा वर्तमान में पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है पर, भविष्य में इसे संस्थान की नीति के अनुसार अत्यधिक रियायती दरों पर दिया जाएगा। निजी प्रयोगशालाओं में यही जांच लगभग छह हजार रुपये से दस हजार रुपये प्रति जांच तक की होती है, जिससे नियमित जांच कराना कई मरीजों के लिए कठिन हो जाता है। इसके साथ ही एम्स ने मिर्गी के मरीज के लिए विशेष दवा मात्रा और नियमित निगरानी सेवा भी आरंभ की है। इसे एम्स के न्यूरोसाइंसेज सेंटर की न्यूरोबायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला ने आरंभ किया है। एम्स की इस नई पहल को मिर्गी के उपचार को 'अनुमान आधारित चिकित्सा' से आगे 'व्यक्तिगत और सटीक चिकित्सा' की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एम्स न्यूरोसाइंसेज केंद्र (एनएससी) के प्रमुख प्रो. डा. एसबी गायकवाड़ ने बताया कि न्यूरोबायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला में आरंभ की गई इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मिर्गी के इलाज को अधिक सटीक और व्यक्तिगत बनाना है। इसके तहत अब डाक्टर मरीज के शरीर में दवा की वास्तविक मात्रा की जांच करके यह तय करेंगे कि रोग के लिहाज से उसे कितनी दवा दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर मरीज को मरीज की स्थिति के अनुसार उन्हें दवा की अलग-अलग दवा मात्रा मिलेगी, न कि एक समान खुराक। दावा है कि इससे उपचार अधिक प्रभावी तो होगा ही साथ ही दवा की अधिक या कम मात्रा से होने वाले दुष्प्रभाव भी कम होंगे। बताया कि इसके लिए चिकित्सीय औषधि निगरानी व्यवस्था भी बनाई गई है। यह बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और आंतरिक रोगी विभाग (आइपीडी) दोनों के लिए है। एम्स न्यूरोबायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला प्रभारी प्रो. डॉ. अशोक शर्मा के अनुसार इसके लिए मरीज के रक्त में एक से तीन मिलीलीटर नमूना लेकर जांच की जाएगी। रिपोर्ट अस्पताल के इलेक्ट्रानिक पोर्टल और रोगी सेवा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। साथ ही मरीजों की समय-समय पर जांच करके दवा की मात्रा में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे, यह प्रक्रिया निरंतर निगरानी पर आधारित होगी।